भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4536

दिनांक 20.08.2025 को उत्तर देने के लिए

नीति आयोग की रिपोर्ट 2014-15

4536. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग की 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित कई सीटें योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सकीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित कई रिक्तियां पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सकीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या नीति आयोग की 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की शैक्षिक स्थिति मुख्यधारा के समुदायों से बेहतर नहीं है और यदि हां, तो क्या सरकार का अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सामाजिक-शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप-योजना की तर्ज पर एक विशेष कार्य योजना शुरु करने का विचार है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ग) उद्धृत रिपोर्ट में प्रस्तुत विवरण 10 वर्ष पूर्व की अवधि का है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नामांकन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अखिल भारतीय

उच्च शिक्षण सर्वेक्षण (एआईएसएचई) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ओबीसी के नामांकन में निरंतर वृद्धि हुई है:

वर्ष	2016-17	2018-19	2020-21	2021-22
ओबीसी नामांकन	1,22,99,309	1,35,91,994	1,48,21,537	1,63,36,460

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार ने निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से ओबीसी समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई पहल की हैं।

i. केंद्र सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में, ओबीसी को 27% आरक्षण उपलब्ध है।

ii. ओबीसी वर्ग के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति।

iii. कक्षा 11 और 12 के ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति।

iv. युवा उपलब्धि योजना (श्रेयस) (ओबीसी और अन्य) के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।

v. जीवंत भारत के लिए प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम-यशस्वी)।

vi. ओबीसी वर्ग के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप।

vii. ओबीसी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।

viii. ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी वर्ग के कौशल विकास के लिए सहायता।

ix. ओबीसी वर्ग के लिए वेंचर कैपिटल फंड का शुभारंभ।

x. ओबीसी वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की कम ब्याज दर पर ऋण/वित्त सहायता स्कीमें।

ख) उद्धृत रिपोर्ट में दिया गया कथन 10 वर्ष पूर्व की अवधि से संबंधित है। बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारणों को दूर करने के उपाय शुरू करने और विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से उन्हें भरने के लिए एक आंतरिक समिति गठित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2016 से अब तक 4 लाख से अधिक बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भरी जा चुकी हैं, जिनमें ओबीसी की 1.55 लाख बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां

शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा की गई सीधी भर्ती में ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी पिछले 10 वर्षों के दौरान लगातार 27% से अधिक रहा है।

उपर्युक्त स्कीमों के अतिरिक्त, सरकार कई ऐसी योजनाएं लागू कर रही है जिनमें संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे ओबीसी समुदायों को भी लाभ होता है। इनमें हर घर जल योजना, पीएम आवास योजना, मिशन इंद्रधनुष, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम पोषण योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई – एनआरएलएम), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई –एनयूएलएम), दीन दयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू- जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस), पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना आदि शामिल हैं।